ई-गवर्नेंस के लिए पारदर्शिता जरूरी: कलाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

'देश धीरे-धीरे तरक्की की ओर जा रहा है। इस सफलता का समस्त श्रेय देश के युवा वैज्ञानिकों, कामगारों और उन विभिन्न प्रशिक्षित लोगों को जाता है, जो देश की उन्नति में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज ई-गवर्नेंस की बात भी जोर-शोर से की जा रही है, जिससे सभी लोगों को देश के प्रशासनिक ढांचे और उसके कदमताल से जोड़ा जा सके। लेकिन इसके लिए ई-गवर्नेंस को केवल अंग्रेजी में ही सीमित न किया जाए। यह भाषा देश के लगभग दस से पंद्रह प्रतिशत लोग ही बोलते हैं। बाकी लोग हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समझते हैं। ऐसे में केवल अंग्रेजी मोह से ही ई-गवर्नेंस बंधा रहा तो उसका कोई बेहतर लाभ नहीं मिलेगा।' राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने उक्त विचार आईआईटी दिल्ली के मैनेजमेंट संकाय द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस' नामक तीन दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए।

इस मौके पर उन्होंने ई-गवर्नेंस पर लिखी दो पुस्तकों के अलावा सेमिनार की जानकारी देने वाली एक स्मारिका का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में बहुउद्देश्यीय नागरिक पहचान पत्र बनने चाहिए, जिससे सरकारी धन के होने वाले अपव्यय पर रोक लग सके। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र के समस्त डाटा को जुटाकर एक-दूसरे को देना चाहिए, जिससे किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के लिए बेवजह की मशक्कत और देरी की संभावना ही न बचे।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ऐसे डाटा की सुरक्षा के लिए कोई फुलप्रूफ सॉफ्टवेयर भी बनाना चाहिए, जिससे उसके दुरुपयोग और गलत हाथों में पड़ने की संभावना को खत्म किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने में आईआईटी अपनी भूमिका बखूबी निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस से देश को एक ढांचागत रूप में जोड़ना होगा, जिसमें शहर को जिला मुख्यालय से और जिला मुख्यालय को ब्लाक व ब्लाक को गांव स्तर से संपर्क करने में कोई दिक्कत न हो।

नई दिल्ली में आईआईटी में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स सम्मेलन का दीप जलाकर उद्घाटन करते राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। श्याम सुंदर